कानपुर, शनिवार, 31 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 32, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड कोहरे का कहर, 11 वाहन भिड़े, 15 घायल...>Pg12
अवैध प्लाटिंग पर 11 बीघा में बुलडोजर एक्शन...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

सोना-चांदी में ऐतिहासिक क्रैश

निवेशकों में हाहाकार

चांदीः एक दिन में 1 लाख रुपए से अधिक की ऐतिहासिक गिरावट
सोनाः 33 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता
बाजारः वायदा और घरेलू सर्राफा बाजार दोनों प्रभावित
मुय कारणः डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड, मुनाफावसूली
बाजारः MCX और घरेलू सर्राफा बाजार दोनों में पड़ा असर

एक ही दिन में चांदी 1 लाख से ज्यादा टूटी, सोना 33 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। कीमती धातुओं के बाजार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वायदा कारोबार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक सोना और चांदी के दाम एक साथ तेज़ी से नीचे आए। एक ही कारोबारी दिन में चांदी का भाव 1 लाख रुपये से अधिक गिर गया, जबकि सोना 33 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट अब तक की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावटों में शामिल है।

गिरावट इतनी तेज रही कि कई प्रमुख सर्राफा बाजारों में खरीद-फरोख्त सीमित करनी पड़ी। तेजी के बाद आई इस अचानक टूटन से निवेशकों, ज्वैलर्स और कारोबारियों में सतर्कता का माहौल बन गया। ऊंचे स्तर पर खरीद करने वाले निवेशकों को एक दिन में भारी नुकसान हुआ है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में गिरावट से उनकी चिंता बढ़ गई है। इन हालातों में छोटे और मध्यम निवेशकों ने नए निवेश से फिलहाल दूरी बना ली है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अल्पावधि में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। आगे की चाल वैश्विक बाजार, डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर निर्भर करेगी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसे करेक्शन के बाद संभावित अवसर माना जा रहा है।

वायदा कारोबार में भारी बिकवाली

- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी में रिकॉर्ड स्तर की गिरावट दर्ज की गई
- सोने के वायदा भाव में भी तेज दबाव और व्यापक बिकवाली देखने को मिली
- कारोबार के दौरान लगातार निचले स्तर बनने से बाजार अस्थिर रहा
- घरेलू सर्राफा बाजार पर सीधा असर
- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और कानपुर सहित प्रमुख बाजारों में सोना-चांदी के दाम तेजी से गिरे
- भावों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण ज्वैलर्स ने नए सौदे रोक दिए
- शादी-ब्याह के सीजन से पहले ग्राहक और कारोबारी दोनों सतर्क दिखे

गिरावट के पीछे प्रमुख कारण

- अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, जिससे सोना-चांदी की मांग कमजोर पड़ी
- अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, सुरक्षित निवेश से पूंजी की निकासी
- लंबे समय से चली आ रही तेजी के बाद तेज मुनाफावसूली
- सोना-चांदी का ओवरबॉट स्थिति में होना, जिससे तकनीकी करेक्शन तेज हुआ
- अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही सोना-चांदी दबाव में कारोबार कर रहे थे
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगे की मौद्रिक नीति को लेकर अनिश्चितता
- वैश्विक निवेशकों का रिस्क-ऑफ रुख, जिससे कमोडिटी प्रभावित

- सोनाः सप्ताह की शुरुआत में 1.35 लाख रुपए 10 ग्राम के स्तर पर था, रविवार 31 जनवरी को गिरावट के साथ 1.60+ लाख रुपए 10 ग्राम पर बंद हुआ । सप्ताह के बीच रिकॉर्ड उछाल के बाद गिरावट का रुख देखा गया।
- चांदीः सप्ताह की शुरुआत 3.35 लाख रुपए किग्रा थी, मध्य सप्ताह में 4.10 लाख रुपए किग्रा तक पहुंची, फिर 31 जनवरी को 3.50 लाख रुपए किग्रा पर ठहराव आया।
- वायदा बाजार (MCX) के रेट भी इस गिरावट के रुझान के अनुरूप नीचे आए हैं। जैसे 31 जनवरी को सोना 1,50,849 रुपए 10 ग्राम और चांदी 2,91,922 रुपए किग्रा के करीब कारोबार हुआ।

सोना-चांदी के भाव – पिछले एक सप्ताह में

तारीख	सोना (24K) - 10 ग्राम	चांदी रुपए /किग्रा
24 जनवरी 2026	,36,210 के आसपास	3,35,000 के आसपास
25 जनवरी 2026	लगभग 1,35,000+	लगभग 3,35,000+
26 जनवरी 2026	करीब 1,37,000	करीब 3,60,000+
27 जनवरी 2026	1,61,950	3,75,000
28 जनवरी 2026	लगभग 1,62,000+	लगभग 3,80,000+
29 जनवरी 2026	रिकॉर्ड स्तर 1,83,000+	रिकॉर्ड स्तर 4,10,000+
30 जनवरी 2026	करीब 1,79,000	3,66,000
31 जनवरी 2026	1,60,580	3,50,000

(नोटः सभी रेट रुपयों में)

जीएसटी चेकिंग के नाम पर व्यापारियों का हो रहा उत्पीड़न

दो दिन बाद व्यापार मंडल के दबाव में छोड़ी गई व्यापारी की गाड़ी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जीएसटी जांच के नाम पर व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने का एक और मामला सामने आया है। धनकुट्टी स्थित फर्म सिमरन इंटरप्राइजेज की गाड़ी, जिसके सभी कागजात पूर्ण थे और टैक्स का भुगतान किया जा चुका था, उसे जीएसटी अधिकारी संतोष कुमार द्वारा जबरन रोके रखा गया।

जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर से धनकुट्टी तक मात्र 4 किलोमीटर के भीतर माल स्थानांतरण को आधार बनाकर व्यापारी की गाड़ी को जीएसटी मुख्यालय में 2 दिनों तक खड़ी करवा दिया गया। इस दौरान व्यापारी को मानसिक और आर्थिक रूप से भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

मामले को लेकर आज अपर आयुक्त ग्रेड 2 से तीखी नोंकझोंक हुई, जिसके बाद दबाव में आकर पीड़ित व्यापारी की गाड़ी को तत्काल छोड़ना पड़ा। व्यापारियों का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई उत्पीड़न की मंशा से की गई थी, न कि किसी वास्तविक कर चोरी के संदेह में।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

व्यापारी संगठनों से जुड़े -पंडित शेष नारायण त्रिवेदी, मुकुल वर्मा, राजू चौधरी, किशोर सक्सेना, हरिकिशन त्रिपाठी, राजेश त्रिवेदी, दीपक खन्ना, ओमप्रकाश मिश्र, दिनेश गुप्ता सहित अन्य का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई बार जीएसटी चेकिंग के नाम पर वैध कागजात होने के बावजूद गाड़ियों को रोका गया, घंटों खड़ा रखा गया और व्यापारियों को बेवजह कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। कई मामलों में बाद में बिना किसी कार्यवाही के गाड़ियां छोड़ दी गईं, जिससे स्पष्ट होता है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

व्यापारियों में रोष-लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस प्रकार की कार्यवाही से व्यापार करना कठिन होता जा रहा है और प्रशासन पर से भरोसा कमजोर पड़ रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि जीएसटी जांच के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं और वैध व्यापारियों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हो।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध के चलते कानपुर में उग्र प्रदर्शन

प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी किए गए नए नियमों के विरोध में 30 जनवरी 2026 को सरसैया घाट गेट, कानपुर पर शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति (पंजीकृत), अखिल भारतीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा (पंजीकृत) तथा 24 अन्य सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को संविधान में निहित समानता, निष्पक्ष न्याय और समता की मूल भावना के विपरीत बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगाए जाने को एक गंभीर संवैधानिक संकेत बताया।आयोजकों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी करते हुए नियमों के कई प्रावधानों को अस्पष्ट तथा दुरुपयोग की संभावना वाला माना है और इनके प्रारूप को पुनः तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी तथा तब तक पूरे देश में वर्ष 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।प्रदर्शन के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि भेदभाव की परिभाषा सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू की जाए, समानता से संबंधित समिति की संरचना संतुलित, समावेशी और निष्पक्ष बनाई जाए, झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं तथा आवश्यक संशोधन पूर्ण होने तक इन नियमों को लागू न किया जाए।

इस अवसर पर सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह आंदोलन किसी जाति या समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि संविधान, निष्पक्ष न्याय और विश्वविद्यालय परिसरों में वास्तविक समता के समर्थन में है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुधीर द्विवेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम सामान्य वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। जब तक कानून और नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक समता और न्याय केवल कागजों तक सीमित रहेंगे।वहीं महेश मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि कानपुर के सभी सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों से आग्रह है कि वे इस कानून के विरोध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2026 के खिलाफ गठित मोर्चे से जुड़कर संविधान विरोधी प्रावधानों का एकजुट होकर विरोध करें।कार्यक्रम में महेश मिश्रा, अजय कुमार द्विवेदी, सुधीर द्विवेदी, गोपाल दीक्षित, अर्जित गुप्ता, रवि शंकर तिवारी, रजत मिश्रा, आकाश ठाकुर सहित कानपुर के 24 संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कानपुर में अवैध प्लाटिंग 11 बीघा में बुलडोजर एक्शन

कटरी ख्यौरा, बनियापुरवा क्षेत्र में पानी की टंकी के पास की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। प्रवर्तन जोन-1बी की टीम ने लगभग 11 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में कटरी ख्यौरा, बनियापुरवा क्षेत्र में पानी की टंकी के पास की गई। मौके पर बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना अनुमति के विकसित की जा रही प्लाटिंग पर 03 जेसीबी मशीनों के माध्यम से ध्वस्तीकरण किया गया।

ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध रूप से बनाए गए निर्मित, अर्द्धनिर्मित और निर्माणाधीन भवनों के साथ सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट सहित सभी संरचनाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गईं।

इसके साथ ही प्राधिकरण की टीम ने अन्य क्षेत्रों में चल रहे अवैध विकास कार्यों को भी चिन्हित करते हुए संबंधित निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया। प्रतापपुर हरी क्षेत्र में लगभग 3500 वर्गमीटर, सण्डीला क्षेत्र में लगभग 2500 वर्गमीटर तथा अन्य स्थान पर लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लाटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय अवर अभियंता, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकी।

विशेष कार्याधिकारी ने जानकारी दी कि नवाबगंज, कल्यानपुर और बिठूर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्रामों में लगभग 16 बीघा क्षेत्रफल की अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया जा चुका है, जिन पर शीघ्र ही सख्त कार्यवाही प्रस्तावित है।

कानपुर विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ भविष्य में भी निरंतर अभियान चलाया जाएगा और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता की मुहिम

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराई पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और संवाद सामाजिक संगठन ने संयुक्त रूप से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों के भीतर यात्रियों को सतर्क और जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान बैनर, पोस्टर और छोटी-छोटी जागरूकता सभाओं के माध्यम से यात्रियों को मानव तस्करी के तरीकों, तस्करों की पहचान और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। खास तौर पर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाए जाने की आशंका पर जोर देते हुए यात्रियों से सजग रहने की अपील की गई। आरपीएफ और संवाद सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने यात्रियों को बताया कि यदि किसी बच्चे या महिला के साथ असामान्य या संदिग्ध व्यवहार दिखाई दे, अथवा तस्करी की आशंका हो, तो बिना किसी हिचक के रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत सूचना दें। समय पर दी गई सूचना कई ज़िंदगियों को सुरक्षित कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में आमजन की भागीदारी सबसे अहम है। यात्रियों की सतर्कता और सहयोग से रेलवे परिसरों में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

⇨ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और संवाद सामाजिक संगठन की संयुक्त पहल

- कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ऋक्कस्न व संवाद सामाजिक संगठन का संयुक्त अभियान
- स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में यात्रियों को किया गया जागरूक
- बैनर, पोस्टर और जनसंवाद के ज़रिए दी गई जानकारी
- बच्चों व महिलाओं की तस्करी रोकने पर विशेष फोकस
- संदिग्ध गतिविधि दिखने पर 139 हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील

टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का भव्य स्वागत छात्रों में खेलों के सपनों की नई उड़ान

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शनिवार को केडीएमए इंटरनेशनल स्कूल में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पहुंचते ही स्कूल परिसर उत्सव में बदल गया। छात्रों ने 'भारत माता की जय' के नारों और तालियों के बीच ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर यूपी टी20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रॉफी लेकर स्कूल पहुंचे। यह ट्रॉफी यात्रा उन स्कूलों तक पहुंचाई जा रही है, जहां से देश के खिलाड़ी निकले हैं, ताकि नई पीढ़ी खेलों के प्रति प्रेरित हो सके। छात्रों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए खासा उत्साह दिखाया।

स्कूल परिसर को टी20 वर्ल्ड कप के कटआउट और क्रिकेट स्टार कुलदीप यादव की तस्वीरों से सजाया गया। कुलदीप ने अपने करियर की शुरुआत इसी स्कूल से की थी।

⇨ कुलदीप यादव की स्कूल में ट्रॉफी पहुंचने पर 'भारत माता की जय' से गूंजा परिसर, छात्र उत्साह से झूमे

छात्रा जानवी के लिए यह पल खास रहा, क्योंकि उन्हें कुलदीप यादव के पिता से मिलने का अवसर मिला।

डॉ. संजय कपूर ने कहा, "कुलदीप का केडीएमए है और केडीएमए का कुलदीप।" छात्रों ने टीम इंडिया की जीत का भरोसा जताया। छात्र अनुभवी और अर्पिता ने कहा कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जीत का परचम टीम इंडिया ही लहराएगी। कानपुर के लिए यह शनिवार लंबे समय तक यादगार रहेगा, जिसे केडीएमए के छात्र और शिक्षक संजोकर रखेंगे।

- टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के स्वागत पर स्कूल परिसर 'भारत माता की जय' से गूंज उठा।
- कुलदीप यादव की स्कूल से शुरुआत और उनकी तस्वीरों ने छात्रों में प्रेरणा जगाई।
- छात्राओं ने टीम इंडिया की जीत पर पूरा भरोसा जताया।
- डॉ. संजय कपूर ने टीम इंडिया की लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद जताई।
- छात्र और शिक्षक इस आयोजन को लंबे समय तक याद रखेंगे।

नगर निगमः सेवानिवृत्ति के दिन ही मिला पूरा भुगतान

नगर आयुक्त की पहल से 16 कर्मचारियों के चेहरे खिले

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब अपने देयकों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शनिवार को नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए 16 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया। देयकों के साथ पेंशन बुक भी कर्मचारियों को सौंप दी गई।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की चेक तथा आरटीजीएस प्रक्रिया के माध्यम से उपादान, अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया। इस अवसर पर 07 सफाई कर्मचारी, 02 लिपिक, 03 बेलदार, 01 स्विचमैन, 01 भिस्ती, 01 ग्रेव डिगर तथा 01 चपरासी सेवानिवृत्त हुए। नगर आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों के देयकों के प्रति नगर निगम पूरी तरह सजग है। कर्मचारियों के योगदान के कारण ही नगर निगम आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है। जनवरी माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए समिति गठित कर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पूरे कर दिए जाएं। अब कर्मचारियों को न तो बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि लंबित देयकों के निस्तारण के लिए गठित समिति प्रत्येक 15 दिन में बैठक कर निर्णय लेगी। कार्यक्रम में उपादान मद में 1,49,01,900, भविष्य निधि में 56,90,358 तथा अवकाश नगदीकरण में 1,02,77,900 का भुगतान किया गया।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने समय पर भुगतान मिलने पर संतोष व्यक्त किया और नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार जताया।

एडीएम सिटी ने सदर तहसील का किया निरीक्षण

» नाजिर से पूछा-नाजिर का क्या अर्थ होता है?

» शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समय से करने का आदेश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । एडीएम सिटी ने शनिवार को सदर तहसील का निरीक्षण किया। पटलों के साथ लेखपालों से कार्य संबंधी जानकारी ली। फरियादियों से बात की और शिकायत निस्तारण का आदेश दिया। गंदगी देख एडीएम सिटी ने नाजिर से पूछा नाजिर का क्या अर्थ होता है।एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि राजस्व कार्य में तेजी, फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समय से, सफाई को लेकर नगर निगम को लेटर लिखने का आदेश दिया है।एडीएम सिटी ने सदर तहसील में आने वाले फरियादियों की परेशानी सुनी और इसे जल्द निस्तारण को निर्देशित किया। इसके बाद तहसील के कार्यालयों का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों से बात की और परेशानी जानी। शौचालय की सफाई और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को कहा है।उन्होंने तहसील के लेखपालों, संग्रह अमीनों, पटल सहायकों व नायब तहसीलदारों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि शिकायतों, राजस्व कार्यों, वादों और वसूली से संबंधित कार्यों को तत्परता से गुणवत्तापरक व समय से निपटाया जाए। इसके साथ ही तहसील के संग्रह अनुभाग, खतौनी सेक्शन व अन्य पटलों और न्यायालयों का एडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम सदर अनुभव सिंह, तहसीलदार विनय द्विवेदी और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

6 साल, 18 तारीखें ,18 नोटिस

पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए जारी है कोशिश

» छह साल से लंबित पुलिस बैरक हादसा मामला, अधिकारियों की चुप्पी पर आयोग सख्त

» पुलिस लाइन बैरक हादसे में पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए पंकज कुमार सिंह ने 6 साल पहले दाख़िल की थी एनएचआरसी में रिट

» मृतक पुलिस कर्मी की बेवा को दिलाया 25 लाख मुआवज़ा, आश्रित माँ को 5 लाख पर घायल पुलिस कर्मियों के न्याय के लिए जारी है लड़ाई, एनएचआरसी कोर्ट ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर पुलिस लाइन में हुए बैरक हादसे को छह साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक घायल पुलिसकर्मियों को मुआवज़ा नहीं मिल सका है। इस गंभीर लापरवाही पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।यह निर्देश याचिकाकर्ता कानपुर के इंजीनियर पंकज कुमार सिंह की दलीलों पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी कोर्ट ने दिए।

आयोग ने अधिकारियों से छह सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि हादसे में घायल तीन पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मुआवज़े का क्या हुआ।

आयोग ने यह भी पूछा है कि यदि मुआवज़ा दिया जा चुका है, तो उसके प्रमाण अब तक प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए। यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है। आयोग के अनुसार, हादसे में शहीद हुए सिपाही अरविंद सिंह की पत्नी नीलेश कुमार को 20 लाख और मां प्रेमश्री को 5 लाख मुआवज़ा दे दिया गया है और उसके दस्तावेज भी जमा किए जा चुके हैं, लेकिन घायलों के मामले में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इंजीनियर ने उठाई थी आवाज़

वर्ष 2020 में कानपुर पुलिस लाइन में स्थित करीब 105 साल पुरानी बैरक की छत गिर गई थी। इस हादसे में सिपाही अरविंद सिंह की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे।इंजीनियर पंकज कुमार ने 12 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की थी। लंबे समय बाद आयोग ने मृतक के आश्रितों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया, लेकिन घायलों के मामले में प्रशासन की उदासीनता अब भी बनी हुई है।22 जनवरी को हुई सुनवाई में आयोग ने स्पष्ट नाराज़गी जताते हुए कहा कि यदि मुआवज़ा दिया जा चुका है, तो उसके प्रमाण तुरंत पेश किए जाएँ। आयोग ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए छह सप्ताह की मोहलत दी है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 फरवरी से

» प्रयोगात्मक परीक्षा- 2 फरवरी से शुरू

» 165 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर

» कंट्रोल रूम से जिला स्तर पर निगरानी होगी

» परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड के निर्देशानुसार

» मुख्य परीक्षा-18 फरवरी से, 78 केंद्र तैयार

फर्रुखाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट (प्रयोगात्मक) परीक्षाएं 2 फरवरी से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रयोगात्मक परीक्षा में कोई लापरवाही न बरतें। परिषद ने परीक्षा केंद्रों और पंजीकृत छात्रों की सूची उपलब्ध कराई है।उन्होंने कहा कि 165 परीक्षा केंद्रों में वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे निम्न विवरण शीघ्र जिला विद्यालय निरीक्षक को कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या, प्रयोगशाला संचालन की स्थिति, सीसीटीवी कैमरों की संख्या, डीवीआर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा के दूसरे चरण में दूसरे जिलों से परीक्षक बोर्ड के निर्देश पर परीक्षा लेने आएंगे। परीक्षा की निगरानी जिला कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कंट्रोल रूम का प्रभारी राम लखन पाल होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा के बाद 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षा शुरू होगी। इस बार हाई स्कूल और इंटर के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

सम्पादकीय

परिपक्व उम्र में ही हो सोशल मीडिया तक पहुंच

बच्चों व किशोरों की सोशल मीडिया पर बढ़ती अति-सक्रियता अभिभावकों ही नहीं, देश के लिये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों का पढ़ाई से भटकाव व एकाग्रता में गिरावट समय की बड़ी फिक्र है। इसी बीच इकोनॉमिक सर्वे में सोशल मीडिया तक उम्र के हिसाब से पहुंच का सुझाव एक स्वागत योग्य कदम है। सालों से, डिजिटल विस्तार को एक बिना शर्त अच्छे बदलाव के रूप में देखा जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि सोशल मीडिया तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डिजिटल लिटरेसी की खामियों को दूर करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने में डिजिटल क्रांति सहायक है। निश्चित रूप से आर्थिक सर्वे में इस बाबत उल्लेख एक असहज करने वाली सच्चाई को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह स्वीकार किया जा रहा है कि बिना रोक-टोक के डिजिटल एक्सपोजर तेजी से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है। सही मायनों में डिजिटल लत को मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली समस्या के रूप मे पहचानते हुए, सर्वे इस बहस को तथ्यों पर आधारित नीति बनाने की जरूरत बताता है। इसकी सिफारिश है कि उम्र के हिसाब से एक्सेस की सीमाएं तय करने, उम्र की वेरिफिकेशन के लिये प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही निर्धारित करने, बच्चों के लिये सरल डिवाइस बनाने और ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। सही मायनों में इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति का ही अनुसरण किया जा रहा है। वास्तव में बच्चों को सम्मोहित करने वाले डिजिटल डिजाइनों से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। जो कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों पर खासा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। निश्चित रूप से डिजिटल लत के शिकार होते बच्चों व किशोरों के, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्धारण समय की मांग है। इसके अलावा इस बाबत सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देना भी उतना ही जरूरी है। तभी इस संकट का आशाजनक समाधान तलाशना संभव हो सकेगा।

वहीं दूसरी ओर, इस संकट से उबरने के लिये प्लेटफॉर्म लेवल सेफ्टी और फैमिली डेटा प्लान की भी मांग की जा रही है। जो पढ़ाई की जरूरत और मनोरंजन के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल का फर्क कर सके। इसके साथ ही हालिया आर्थिक सर्वे में इस बात को स्वीकार किया गया है कि माता-पिता पहले से ही यह जानते हैं कि व्यक्तिगत कंट्रोल बड़े पैमाने से इस समस्या का समुचित हल नहीं निकाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि आस्ट्रेलिया व फ्रांस जैसे विकसित देशों में सरकारों को इस दिशा में सख्त पहल करनी पड़ी। एक ओर जहां आस्ट्रेलिया ने सोलह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगायी है, वहीं फ्रांस ने पंद्रह साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोशल मीडिया तक सीधी पहुंच को रोकने को कदम उठाये हैं। कुछ अन्य देशों में भी सरकारें तेजी से सख्त सीमाएं तय करने की दिशा में काम कर रही हैं। आज जहां भारत में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। वैसे भारत जैसे देश जहां युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां डिजिटल क्रांति से पूरी तरह अलग भी नहीं रहा जा सकता। ऐसे में एक नियम से ही सबको नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद हमें स्वीकारना होगा कि विदेशी प्लेटफॉर्मों से प्रसारित अपसंस्कृति भारतीय किशोरों को पथभ्रष्ट करने में घातक भूमिका निभा रही है। जिससे देश में किशोरों की यौन अपराधों में संलिप्तता का खतरा बढ़ रहा है। ये अपसंस्कृति न केवल समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रही है, बल्कि उनमें मानवीय संवेदनाओं का भी क्षरण कर रही है। जो किसी भी सभ्य समाज के लिये एक गंभीर चुनौती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक मूल्यों व संबंधों में शुचिता को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है।

इस बाबत सरकार की सख्त पहल और अभिभावकों की सजगता मिलकर ही समस्या का समाधान निकाल सकती है।

श्रमिक-किसान कल्याण हो जीडीपी का पैमाना

पुष्परंजन

जीडीपी वृद्धि की प्रत्येक इकाई अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण भी बन रही है। इसलिए, भारत उस शहरी-औद्योगीकरण विकास मॉडल का पालन जारी रखना गवारा नहीं कर सकता, जिसने वैश्विक पर्यावरण और असमानता..जीडीपी वृद्धि की प्रत्येक इकाई अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण भी बन रही है। इसलिए, भारत उस शहरी-औद्योगीकरण विकास मॉडल का पालन जारी रखना गवारा नहीं कर सकता, जिसने वैश्विक पर्यावरण और असमानता संकट पैदा किए हैं। भारत के नीति-निर्माता दुविधा में हैं। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, जिसको इसमें कार्यरत लोगों की संख्या के हिसाब से मापा जाता है, वह बहुत कम है। उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों एवं खेतों से और लघु, 'अनौपचारिक' कारखानों और सेवा उद्यमों से भी निकालकर शहरों में लाया जाए ताकि उन्हें बड़े, 'औपचारिक' कारखानों एवं सेवा उद्यमों में काम पर लगाया जा सके। समस्या यह है कि बड़े औपचारिक उद्यम पर्याप्त सुरक्षित नौकरियां और अच्छा वेतन नहीं दे रहे हैं।

वे ज़्यादा लोगों को काम पर रखने, उन्हें अधिक तनख्वाह और सामाजिक सुरक्षा देने को तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय, वे वेतन की लागत कम रखने के लिए अधिक 'लचीले' श्रम कानूनों की मांग कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या यह है कि सभी क्षेत्रों मसलन, विनिर्माण, सेवाएं और कृषि में नियोक्ता अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंसानों के बजाय ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस मुख्य सुधार की ज़रूरत है, वह है व्यावसायिक उद्यम के ढर्रे और प्रचालन में सुधार। मज़दूर, चाहे वे खेतों में हों या कारखानों में, वे जिस उद्यमों में काम करते हैं उनके मालिकों की सोच होती है, उनके काम से हुआ मुनाफ़ा, उनका ही रहे और उनकी संपत्ति में इजाफा करे, न कि यह लाभ किसी वित्तीय निवेशक की संपत्ति बढ़ाने के काम आए। उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक पूंजीगत संपत्ति जैसे कि विनिर्माण उद्यम में मशीनें और खेती के लिए ज़मीन, उद्यम में काम करने वाले मज़दूरों की होनी चाहिए। मज़दूर अपने मालिक खुद हों और उन्हें स्टॉक मार्केट निवेशकों और सामंती ज़मींदारों की मल्कियत वाले कारखानों और खेतों में कर्मचारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अपने काम से होने वाले मुनाफ़े का इस्तेमाल वह कैसे करेंगे, यह चुनने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। अब चाहे तो अपने उद्यम में और अधिक निवेश करें या अपने परिवार के कल्याण और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं।जैसा कि माइक बर्ड ने अपनी किताब 'द लैंड ट्रैप ⁼ए न्यू हिस्ट्री ऑफ़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एसेट' नामक पुस्तक में बताया है कि भू-स्वामित्व में सुधार, जिसके तहत ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर उनके खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को हस्तांतरित की गई, उसकी बदौलत पिछले 50 सालों में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में छोटे किसानों की आय भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। बर्ड व्याख्या करते हैं कि भारत की तुलना में अन्य देशों में सुधार तेज़ी से क्यों हुए। सभी देशों में निहित स्वार्थ सुधारों के रास्ते में आड़े आते हैं।

हालांकि, उन देशों के नेताओं ने किसान-मज़दूरों के अधिकारों का समर्थन किया, न कि पूंजीपति-मालिकों का। सुधारों से छोटे किसानों की कमाई और संपत्ति बढ़ी, और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा निवेश किया। गौरतलब है कि लोगों को खेती से हटाए बिना भी, कृषि-उत्पादन और कृषि उत्पादकता बढ़ी है।

अर्थशास्त्रियों और व्यापार करने वालों को उद्यमों में 'पैमाने' पर फिर से सोचना चाहिए। एक मानकीकृत वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन, चाहे यह फैक्टरी उत्पादन बढ़ाने में सहायक कोई प्रक्रिया हो या बड़े खेत में एक ही फसल उगाना, बड़ी मशीनों का उपयोग और दोहराव वाले कामों को करने के लिए कम कुशल श्रमिकों को रोज़गार देकर अपनी आर्थिक दक्षता बढ़ाता है।

बड़े पैमाने के उद्यमी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूंजी लगाने की हैसियत रखते हैं। इस तरह, उन्हें कम श्रमिक और बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करके जहां उनकी दक्षता और उत्पादन मात्रा बढ़ सकती है, और उत्पादकता भी। ऐसे उद्यम कम श्रमिकों को नौकरी पर रखते हैं। वे अर्थव्यवस्था के 'रोजगार रहित' सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी से योगदान करते हैं। छोटे खेत जो जैविक तरीके से उन्नत किस्म की फसलें उगाते हैं, उन खेतों में उत्पादन की 'संभावना' ज़्यादा होती है। कचरा खेत में अपने आप उपयोगी अवयव बन जाता है, खासकर उन खेतों में जहां पर जानवर भी रखे होते हैं। ज़्यादा संभावना वाले खेत स्वाभाविक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं।

अदालती चौखट पर नूरा-कुश्ती की हकीकत

कलूसिव सूट

डा0 सुधीर कुमार

जब दो पक्ष हाथ मिलाकर अदालत के सामने दिखावटी लड़ाई करते हैं, तो उसे 'कलूसिव सूट' कहते हैं। इसे 'साजिशी मुकदमा' कहना सटीक होगा।न्यायपालिका वह पवित्र स्थान है जहां सत्य की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आज 'कलूसिव सूट' (साजिशी मुकदमों) के जरिए इस मंदिर की गरिमा को चुनौती दी जा रही है। यह कानूनी जगत का वह अंधेरा कोना है जहां वादी और प्रतिवादी विरोधी होने का मात्र ढोंग करते हैं, जबकि हकीकत में वे एक ही 'साजिशी पटकथा' के किरदार होते हैं। जब न्याय की गुहार लगाने वाला और उसका विरोध करने वाला, दोनों ही परदे के पीछे एक हो जाएं, तो अदालत का कठघरा केवल एक रंगमंच बनकर रह जाता है। न्याय की बुनियादी अवधारणा को ठेस पहुंचती है। ऐसी कृत्रिम लड़ाइयां न केवल न्यायिक समय की बर्बादी हैं, बल्कि उन वास्तविक शोषितों का हक भी मारती हैं जो न्याय की कतार में अंतिम पायदान पर खड़े हैं।

सरल शब्दों में कहें तो जब दो पक्ष आपस में हाथ मिलाकर अदालत के सामने 'नूरा-कुश्ती' (दिखावटी लड़ाई) करते हैं, तो उसे कानून में 'कलूसिव सूट' कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे 'साजिशी मुकदमा' कहना ज्यादा सटीक होगा। यह एक ऐसा कृत्रिम विवाद है जहां दोनों पक्ष वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं होते और उनके बीच कोई वास्तविक कानूनी संघर्ष नहीं होता। वे अदालत की चौखट पर सिर्फ इसलिए पेश होते हैं ताकि आपसी साजिश के जरिए एक ऐसी 'डिक्री' या सरकारी आदेश हासिल कर सकें, जिसे वे ईमानदारी के रास्ते से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे।हमारी भारतीय न्याय प्रणाली 'प्रतिद्वंद्वी पद्धति' पर आधारित है, जिसका मूल सिद्धांत ही यह है कि जब दो विरोधी पक्ष पूरी शिद्दत से अपनी बात और दलीलें रखेंगे, तभी सत्य छनकर बाहर आएगा। लेकिन जब विरोध ही दिखावटी हो और दोनों पक्ष 'मेज के नीचे' हाथ मिला चुके हों, तो अदालत महज एक मूकदर्शक बनकर रह जाती है। निस्संदेह, यह उस पवित्र तंत्र की तौहीन

भी है जिसे समाज में न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया है। कानून की नजर में 'मिलीभगत' के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 40 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि कोई फैसला, आदेश या डिक्री 'धोखे' या 'मिलीभगत' से प्राप्त की गई है, तो उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। यह धारा एक सुरक्षा कवच है। इसके अलावा, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अदालतों को यह अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है कि वे ऐसे मुकदमों को पहचानते ही खारिज कर दें। कानून का एक वैश्विक सिद्धांत है- धोखे से कभी भी कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं हो सकता।

भारतीय न्यायपालिका ने हमेशा से इन साजिशी मुकदमों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इस दिशा में 'नगुबाई अम्मल बनाम बी. शमा राव' (1956) का फैसला एक नजीर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'साजिश' और 'धोखे' के बीच के महीन अंतर को स्पष्ट किया। अदालत के अनुसार, 'फ्रॉड' में एक पक्ष दूसरे को छलता है, किंतु 'कलूज़न' में दोनों पक्ष मिलकर अदालत के साथ छल करते हैं। जब वादी और प्रतिवादी के बीच कोई वास्तविक विवाद न हो और उनका एकमात्र उद्देश्य न्याय की आड़ में किसी तीसरे पक्ष का हक मारना हो, तो वह पूरी तरह 'साजिश' है। इसी प्रकार, 'रूपचंद गुप्ता बनाम रघुवंश कुमार' (1964) में अदालत ने आगाह किया कि यदि डिक्री का उद्देश्य किसी किराएदार या हकदार का अधिकार मारना है, तो वह डिक्री बातिल (शून्य) होगी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि न्याय के सिंहासन पर बैठी अदालतें केवल कागजी सबूतों को नहीं तौलतीं, बल्कि मुकदमों के पीछे छिपी बदनियती को पहचानने की कुव्वत भी रखती हैं।

लोग ऐसा जोखिम अक्सर निजी स्वार्थ के लिए उठाते हैं, जैसे टैक्स चोरी, बैंक के कर्ज से बचना या अवैध कब्जा करना। इसका सबसे बड़ा खमियाजा उस 'तीसरे पक्ष' को भुगतना पड़ता है जो अनजाने में अपना कानूनी हक खो देता है; जैसे पिता-पुत्र की मिलीभगत बैंक के अधिकार को खत्म कर सकती है। यहां 'मैत्रीपूर्ण मुकदमे' (धारा 90, नागरिक प्रक्रिया संहिता) और 'साजिशी मुकदमे' के बीच की 'कुत्सित मंशा' को समझना लाजिमी है। जहां मैत्रीपूर्ण वाद कानूनी स्पष्टता के लिए होते हैं, वहीं साजिशी मुकदमे का उद्देश्य 'अधिकार का अपहरण' करना होता है। इसी महीन लकीर को पहचानना ही एक न्यायाधीश की असल परीक्षा है।एक वकील के लिए उसका पेशा केवल जीविका नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। वकीलों को यह समझना होगा कि वे 'ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट' हैं, न कि किसी साजिश के पटकथा लेखक। यदि कोई अधिवक्ता जानते हुए भी ऐसे फर्जी मुकदमों का हिस्सा बनता है, तो बार काउंसिल को ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

चौबेपुर में सिस्टम फेल, डीएम के निरीक्षण में खुली पोल

सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं की हकीकत परखने पहुंचे डीएम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार अपराह्न चौबेपुर ब्लॉक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की बदहाल स्थिति, साफ-सफाई की भारी कमी और कर्मचारियों की गैरमौजूदगी सामने आने पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीएम को निरीक्षण में विकास खंड कार्यालय परिसर की स्थिति बेहद असंतोषजनक मिली। कई कक्षों में रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी, शौचालय गंदे मिले और प्रेरणा कैंटीन बंद थी। निरीक्षण के समय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत, बीटीए, सहायक अभियंता (आरईएस) ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति पंजिका में भी गंभीर अनियमितता सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा। लेखा कक्ष में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, सामुदायिक शौचालयों में गंदगी और पानी की कमी के मामले में पूर्व निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं मिलने पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी और एडीओ (पंचायत) के जनवरी माह के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए।

➪ अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन कटौती, अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब

सीएचसी चौबेपुर में 10 स्वास्थ्यकर्मी नदारद

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर का निरीक्षण किया। यहां 10 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, एक्स-रे कक्ष, प्रयोगशाला का जायजा लिया। एमओआईसी के अनुसार शुक्रवार को 170 मरीजों का ओपीडी में इलाज किया गया। डीएम ने मरीजों और तीमारदारों से सीधे संवाद कर सुविधाओं की जानकारी भी ली।

विशेष पुनरीक्षण अभियान में भी खामियां

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सुनवाई के दौरान फार्म-6 की उपलब्धता नहीं होने की शिकायत सामने आई। डीएम ने एसडीएम बिल्हौर और बीडीओ चौबेपुर को सभी सुनवाई स्थलों पर फार्म की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।साथ ही कार्यालय कक्षों तक रैम्प की व्यवस्था, खराब कंप्यूटर व प्रिंटर शीघ्र दुरुस्त कराने के आदेश दिए।

निरीक्षण की भनक से तहसील प्रशासन सतर्क

डीएम के संभावित दौरे की सूचना पहले से मिलते ही तहसील स्तर के अधिकारी-कर्मचारी सतर्क नजर आए। कार्यालयों में साफ-सफाई और व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद चलती रही, वहीं लेखपाल अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर लंबित कार्यों के निस्तारण में जुटे दिखाई दिए।

> जनस्वास्थ्य और जनसेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
>
> - जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी

- डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने चौबेपुर ब्लॉक व सीएचसी का औचक निरीक्षण किया
- विकास खंड कार्यालय में गंदगी, अव्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का अभाव उजागर
- एडीओ (पंचायत), बीटीए और एई (आरईएस) निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिले
- उपस्थिति पंजिका में अनियमितता, बीडीओ से दो दिन में स्पष्टीकरण तलब
- लेखा कक्ष में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित पाई गई
- शौचालयों में गंदगी और पानी की कमी, पूर्व निर्देशों की अनदेखी सामने आई
- बीडीओ व एडीओ (पंचायत) के जनवरी माह के वेतन पर रोक के निर्देश
- विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में फार्म-6 की कमी की शिकायत
- सभी सुनवाई स्थलों पर फार्म उपलब्ध कराने के आदेश
- सीएचसी चौबेपुर में 10 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारद
- अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश
- शुक्रवार को सीएचसी ओपीडी में 170 मरीजों का उपचार
- डीएम ने मरीजों व तीमारदारों से सीधे संवाद कर जानी जमीनी हकीकत
- डीएम का सख्त संदेश लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई तय

रौतापुर कलां शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने लिया भंडारे का आनंद

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर क्षेत्र के रौतापुर कलां स्थित प्राचीन शिव मंदिर ने रविवार को वार्षिक उत्सव के माध्यम से स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में अपनी अहमियत दोबारा जताई। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने न केवल पूजा की, बल्कि भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर सामुदायिक भावनाओं को भी साझा किया।मंदिर के कार्यवाहक कमल स्वरूप मिश्रा ने बताया कि कई सदियों पहले शिवजी की लाट का स्वप्नदर्शन हुआ था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार 22 साल पहले 30 जनवरी को किया गया था, और तभी से यह दिन वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

भंडारे और पूजा के अवसर पर गांव के कई बुजुर्ग, युवा और समाजसेवी उपस्थित रहते हैं, जिससे समुदाय में आपसी मेलजोल और धार्मिक भावना मजबूत होती है। इस बार के उत्सव में घनश्याम मिश्र, बाबू मिश्रा, श्रीकृष्ण, राम प्रकाश, समाजसेवी सौरभ शुक्ला, ऋषभ मिश्रा समेत कई श्रद्धालु शामिल हुए।

"मुझे लगा अब नहीं बचूंगा"

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, अस्थायी दुकानें, बिजली की सजावट और गैस सिलेंडरों के बीच आयोजित विशाल मकनपुर मेले में फायर सर्विस कानपुर नगर की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर जनसुरक्षा की मिसाल पेश की। विभाग की सतर्कता से जहां नदी में हुए एक गंभीर हादसे में युवक की जान बची, वहीं मेले के दौरान कई संभावित दुर्घटनाओं को भी समय रहते टाल दिया गया।

मेले के दौरान स्नान के लिए नदी में उतरे अल्ताफ नामक युवक ने जैसे ही छलांग लगाई, पानी के भीतर मौजूद किसी धारदार वस्तु से उसका पेट फट गया। गंभीर रूप से घायल युवक नदी में ही फंस गया और लगातार खून बहने लगा। हालात इतने नाजुक थे कि कुछ ही मिनटों की देरी उसकी जान ले सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात फायर सर्विस के जवान बृज भूषण ओझा, आदित्य पाठक सहित टीम ने बिना समय गंवाए जोखिम भरे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने घायल युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला और तत्काल एस.एम. हॉस्पिटल मकनपुर पहुंचाया।

समय पर इलाज से बची जान: अस्पताल में युवक का तत्काल ऑपरेशन किया गया। एस.एम. हॉस्पिटल के एमडी डॉ. यासिर अली के अनुसार,"अल्ताफ की हालत बेहद गंभीर थी। पेट फटने के कारण संक्रमण फैल रहा था। यदि समय पर इलाज न मिलता तो जान जाना तय था। फायर सर्विस के जवानों की तत्परता काबिले-तारीफ है"। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

➪ फायर सर्विस की तत्परता से नदी में डूब रहे युवक की बची जान
➪ मकनपुर मेले में फायर सर्विस की सतर्कता बनी सुरक्षा की ढाल

पीड़ित की आपबीती

अल्ताफ ने बताया "मैं पानी में डूब रहा था, पेट से लगातार खून बह रहा था। आसपास कोई मदद नहीं दिख रही थी। लगा अब नहीं बचूंगा। तभी फरिश्तों की तरह फायर विभाग के जवान पहुंचे और मुझे समय रहते अस्पताल पहुंचाया।"

मेले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा एवं अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा के मार्गदर्शन में मेला शुरू होने से पहले ही फायर सर्विस की टीमें रणनीतिक स्थानों पर तैनात की गईं। पूरे क्षेत्र में अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर, फायर एक्सटिंग्विशर, आधुनिक रेस्क्यू उपकरण के साथ लगातार निगरानी की जा रही है।

सुरक्षा से बढ़ा श्रद्धालुओं का भरोसा

मेले में फायर सर्विस की सक्रिय मौजूदगी से श्रद्धालुओं और आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बना रहा। भारी भीड़ के बावजूद विभाग ने अनुशासन, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। फायर सर्विस कानपुर नगर की यह भूमिका केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनसुरक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण बनी। समय रहते की गई कार्रवाई और व्यापक इंतजामों के लिए स्थानीय नागरिकों ने भी फायर सर्विस टीम की खुले दिल से सराहना की है।

मिलकिनपुरवा गांव में

प्रभुराम के जीवन चरित्र में जीने की कला

हिमाचल प्रदेश के आचार्य पंकज जी महाराज ने सुनायी कथा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए सहभागी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बाबा ब्रह्म देव जन जागरण सेवा समिति के तत्वावधान में मिलकिनपुरवा, अकबरपुर स्थित ब्रह्मदेव मंदिर परिसर में आयोजित नव दिवसीय राम कथा का भव्य समापन 31 जनवरी 2026 को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। कथा का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया गया। राम कथा के अंतिम दिवस पर पंकज जी महाराज, नैना देवी हिमाचल प्रदेश के मुखारविंद से भगवान राम के जीवन, चरित्र और आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन आज भी सत्य, धर्म, भक्ति और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है।

कथा के दौरान भगवान राम के बाल्यकाल, माता-पिता के आदर्श चरित्र, अयोध्या के धार्मिक व सामाजिक मूल्यों, वनवास, माता सीता के त्याग, लक्ष्मण की सेवा भावना और हनुमान जी की भक्ति जैसे प्रमुख प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथावाचक ने कहा कि श्रीराम का आदर्श जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज भी प्रेरणास्रोत है।विश्राम दिवस पर राम-रावण युद्ध के बाद लंका विजय, भरत मिलाप, अयोध्या वापसी और भव्य राज्याभिषेक का सजीव वर्णन किया गया। रामराज को आदर्श समाज के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जहां सत्य की विजय और समाज में शांति स्थापित होती है।समापन अवसर पर हवन, पूजन और भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कथा की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथावाचक की विदाई के समय श्रद्धालु भजनों पर भावविभोर होते नजर आए।इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनमें श्यामू शुक्ला, जितेंद्र कुमार यादव, अतुल त्रिपाठी, मोनू मिश्रा, बिपिन शुक्ला, अशोक बाजपेई, गुड्डू त्रिवेदी, लाला राम कठेरिया सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे।

उत्साह के साथ पांच दिवसीय उमंग महोत्सव का समापन

» उमंग महोत्सव में मेधाबियों और खिलाड़ियों का बढ़ाया गया सम्मान

» स्नेहलता कॉलेज में धूमधाम से संपन्न हुआ वार्षिक समारोह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद कानपुर (देहात)। वार्षिक उमंग महोत्सव कार्यक्रम में मंच पर बच्चों ने जिस आत्मविश्वास से देशभक्ति की प्रस्तुतियां दीं हैं जिसे देखकर मन प्रसन्नचित हो गया है। बच्चों ने जिस मनोबल के साथ प्रस्तुति दी है। इससे लगता है कि बच्चे आने वाले समय में कुछ बड़ा करेंगे। यह बात उमंग महोत्सव के समापन अवसर विशिष्ट अतिथि कौशल किशोर गुप्ता ने कही।

शनिवार को रसूलाबाद कस्बे में स्थित स्नेहलता गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पांच दिवसीय उमंग महोत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। जहां बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तो वहीं चार दिन तक चली खेल कूद खेलकूद रंगोली प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता सराग ने सरस्वती पूजन कर विधि विधान से किया। इसके बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत कुमार गुप्ता व विशिष्ट अतिथि स्वामी शरण गुप्ता ने कबड्डी, वालीबाल खो खो की विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि संत कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास है। उमंग महोत्सव व खेल कूद प्रतियोगिता भी शिक्षा क्षेत्र में ही आती है। डॉ अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है इसे जो इसे पियेगा दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को कभी बोझ न समझे। इस नई चीज़ सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़े। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री राम जी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया और सफल कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई दी। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्राचार्य डॉ अमित कुमार गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष देवशरण कमल, उप प्रबंधक प्रवेश यादव छुन्नू क्रीडाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, राजीव शुक्ला, सदस्य जिला पंचायत जनार्दन सिंह ऋषि, शिक्षक डीपी शुक्ला, विमलेश यादव, अजय पाल यादव, सीके त्रिपाठी, दिनेश राजपूत ,संतोष बाजपेई, विमल यादव, अजीत गुप्ता, आलोक वर्मा ,यशपाल सिंह ,सोनू पांडेय,अमित तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कोमल शर्मा ने किया।।

कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत

हमीरपुर। मौदहा कस्बे के बांकी तलैया मोहल्ला में एक दर्दनाक हादसे में 62 वर्षीय बुजुर्ग की कच्ची दीवार गिरने से मौत हो गई। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले धन से अपने कच्चे मकान को पक्का बनवाने का कार्य कर रहा था। इकबाल हुसैन (62) निवासी बांकी तलैया को हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त मिली थी। वह अपने रिहायशी मकान की जर्जर कच्ची दीवार गिरा रहा था। इसी दौरान दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी और वह मलबे के नीचे दब गया ।आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उसे बाहर निकाला। परिजन व स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा ले जाया गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अब गरीब व दुर्बल बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश

» आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित, फर्जी कागजात पर होगी सख्त कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। जनपद में अब गरीब, दुर्बल वर्ग के बच्चों के साथ-साथ कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चों को भी पात्रता के आधार पर निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (त्रक्षश्र) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होगा।

चयन की प्रक्रिया लॉटरी पद्धति से की जाएगी।जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवेदन के दौरान यदि किसी अभिभावक द्वारा फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज लगाए गए, तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीपी सिंह को सभी आवेदनों का पात्रता के अनुसार सत्यापन कर लॉटरी के माध्यम से चयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चयनित बच्चों को नियमानुसार निजी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जाए। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत पारदर्शी तरीके से संचालित हो। गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) कक्षा-1 आरक्षित 25त्न सीटों पर प्रवेश अनिवार्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आरटीई प्रवेश का प्रथम चरण- 02 फरवरी से 16 फरवरी व लॉटरी/आवंटनः 18 फरवरी, 20 फरवरी, 26 फरवरी को होगा। वहीं द्वितीय चरण - 21 फरवरी से 07 मार्च व लॉटरी/आवंटनः 09 मार्च, 11 मार्च तक चलेगा। तृतीय चरणः 12 मार्च से 25 मार्च, लॉटरी/आवंटनः 27 मार्च, 29 मार्च तक होगा।

- योजना की जानकारी अधिकतम पात्र अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश।
- ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए विकासखंड/नगर स्तर पर हेल्प डेस्क की स्थापना।
- लॉटरी के बाद निजी विद्यालयों को निर्धारित समय-सीमा में नामांकन अनिवार्य।
- फर्जी प्रमाण-पत्रों के माध्यम से आवेदन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कल माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में न हो कोई चूकः सीपी जोगेंद्र कुमार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। माघ मेला वर्ष-2026 के आगामी माघी पूर्णिमा के बड़े स्नान पर्व को सफल एवं निर्विघ्न आयोजन के दृष्टिगत तेजतर्रार छवि के कर्तव्यनिष्ठ व न्यायप्रिय बहुचर्चित पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने माघ मेला क्षेत्र में ड्यूटीरत समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।मेले में किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी न हो,इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क रहे और मेले में संदिग्धों पर नजर रखें।पीएसी के गोताखोरों द्वारा भी विशेष नजर रखीं जाएं साथ ही कंट्रोल रूम से मेले की पल-पल की निगरानी होती रहे।कोई भी लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए।बताते चलें पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के शानदार नेतृत्व में करोड़ों की भीड़ के कुशल प्रबंधन का गवाह बना माघ मेला अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिज्ञासा का विषय बनता जा रहा है।उक्त ब्रीफिंग में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ अजय पाल शर्मा,पुलिस अधीक्षक माघ मेला,पुलिस उपायुक्त नगर,पुलिस उपायुक्त गंगानगर,पुलिस उपायुक्त यमुनानगर, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अन्य अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे.

कोहरे में कुछ नहीं दिखा ट्रक से भिड़ गई बस

चालक व परिचालक घायल, यात्री बाल-बाल बचे, उन्हें वैकल्पिक वाहनों से भेजा गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रानियां क्षेत्र में शुक्रवार तड़के घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बनारस जा रही एक बस मैथा मोड़ हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस चालक और परिचालक घायल हो गए, जबकि बस में सवार सभी यात्री बाल-बाल बच गए।

पुलिस के मुताबिक बस संख्या बीआर-28 पी 4082 कम दृश्यता के कारण ट्रक से पीछे से जा टकराई, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि चालक राजवीर निवासी ग्राम बागवाला, जनपद एटा और परिचालक कल्लू निवासी ग्राम बाजना,मथुरा) बस में फंस गए। सूचना मिलते ही थाना रनिया पुलिस और क्षेत्राधिकारी अकबरपुर संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान

चलाकर दोनों घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल अकबरपुर भेजा।

पुलिस ने बस के यात्रियों को वैकल्पिक वाहनों से गंतव्य की ओर रवाना किया। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा।

पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटवाया। रनिया थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी संजय सिंह, अकबरपुर यातायात प्रभारी विवेक यादव और एनएचएआई स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंचा।

बूथ डे पर नए मतदाता जोड़ने को लेकर दिखा लोगों में उत्साह

एसआईआर प्रक्रिया के बाद नाम जोड़ने व नोटिस निस्तारण पर दिया गया जोर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

- सभी बूथों पर एक साथ हुआ बूथ डे का आयोजन
- नए मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष फोकस
- नाम संशोधन व त्रुटि सुधार की प्रक्रिया मौके पर
- नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई और निस्तारण
- आगे भी जारी रहेगा बूथ डे अभियान

रसूलाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सभी बूथों पर बूथ डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ना, नाम संशोधन/त्रुटि सुधार कराना तथा जिन मतदाताओं को नोटिस जारी की गई थी, उनका समयबद्ध निस्तारण करना रहा।

तहसील क्षेत्र के सभी बूथ केंद्रों पर तैनात बीएलओ ने मौके पर बैठकर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान नए वोटर पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम संशोधन, त्रुटि सुधार सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराई गईं। तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत सहित विभिन्न कार्यालयों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की नोटिस का निस्तारण किया गया। रसूलाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के बूथों के सुपरवाइजर रवेंद्र कुमार ने बताया कि आगे भी नियमित रूप से बूथ डे आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ना शेष है, वे शीघ्र आवेदन करें तथा जिनको नोटिस प्राप्त हुई है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस अवसर पर बीएलओ अंकित पाल, कंचन देवी, मीना मिश्रा, शैलजा मिश्रा, संजय यादव, अनुपम देवी, माया देवी, गीता देवी, रज्जन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

राजपुर पुलिस को चेकिंग में मिला भटकता बालक, परिजनों के सुपुर्द

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना राजपुर पुलिस टीम को एक नाबालिग बालक भटकता मिला, जिसकी पहचान कर उसके परिजों को सूचना देकर थाने बुलाया गया।

जहां उन्हें बच्चो सुपर्द कर दिया गया। शुक्रवार रात चेकिंग के दौरान कस्बा राजपुर बाजार में एक 9 वर्षीय बालक अपने परिजनों की तलाश में इधर-उधर भटकता मिला। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने अपना नाम आरुष पुत्र राधेश्याम, निवासी हरहरा रामपुर, भोगनीपुर बताया।

पुलिस टीम द्वारा सी-प्लान एप की सहायता से थाना भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम हरहरा रामपुर के संभ्रांत व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों के माध्यम से संपर्क कर बालक के परिजनों को सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर परिजन थाना राजपुर पहुंचे, जहां आवश्यक औपचारिकताओं के बाद नाबालिग बालक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया।

दुरौली ने तुर्कीमऊ व रसूलाबाद ने डेरापुर को हराकर फाइनल में बनाई जगह

» अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले हुए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के मलासा ब्लॉक स्थित पुलंदर गांव में धूल बाबा क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले गए। पहले सेमीफाइनल में दुरौली की टीम ने तुर्कीमऊ को पराजित किया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में रसूलाबाद की टीम ने डेरापुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

दुरौली और तुर्कीमऊ के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में दुरौली टीम के कप्तान बलराम पांडेय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तुर्कीमऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के मैच में 15.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 153 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दुरौली की टीम ने 13.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दुरौली टीम के खिलाड़ी बबलू ने शानदार प्रदर्शन किया।

दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में रसूलाबाद और डेरापुर की टीमें आमने-सामने रहीं। रसूलाबाद टीम के कप्तान विशाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। रसूलाबाद की टीम ने 19.3 ओवर में सभी विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। जवाब में डेरापुर की टीम 13.2 ओवर में मात्र 93 रन पर सिमट गई। इस तरह रसूलाबाद की टीम ने 119 रनों से जीत दर्ज की। रसूलाबाद टीम के खिलाड़ी विशाल ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।

मैच में अंपायर की भूमिका राधा मोहन, मोहित सिंह परमार व बउआ भदौरिया ने निभाई, जबकि स्कोरर की जिम्मेदारी भरत बाजपेई ने संभाली। कमेंट्री मधुर सिंह चौहान, सुरजीत यादव व बबलू संकवार ने की। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राजावत, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विके तिवारी, पंकज तिवारी, सोनू भदौरिया, चंद्रमोहन आदि मौजूद रहे।

12 फीट का अजगर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अजगर को पकड़ने के बाद सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद। सूलाबादङ्कबिल्हौर मार्ग स्थित सुनारन बगिया के समीप शुक्रवार को लगभग 12 फीट लंबा अजगर निकलने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। अजगर के दिखाई देने से स्थानीय ग्रामीणों व राहगीरों में भय का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इससे पूर्व ग्रामीणों द्वारा सतर्कता बरतते हुए अजगर को पानी से बाहर निकाला गया। वन विभाग कर्मियों ने अजगर को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया।

वन विभाग अधिकारियों के अनुसार अजगर को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की कि इस प्रकार की घटना होने पर स्वयं जोखिम न उठाएं और तत्काल वन विभाग या प्रशासन को सूचना दें। अजगर के रेस्क्यू के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली।

सिकंदरा में एसडीएम ने बूथों का किया औचक निरीक्षण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत विशेष मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कपिल सिंह के मार्गदर्शन में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सिकंदरा, प्रदुमन कुमार ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न बूथ केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

एसडीएम प्रदुमन कुमार ने मुडादेव, मानपुर, रसधान इंटर कॉलेज, जरौली, अमोली कुर्मियां खालागांव और जन कल्याण इंटर कॉलेज, उरसन सहित कई महत्वपूर्ण केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को कड़े निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। बीएलओ घर-घर जाकर संपर्क करें और अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म संख्या 6 (नए मतदाता पंजीकरण) भरवाएं। एसडीएम ने यह भी निर्देश दिया कि भरे गए फॉर्मों की सूची तैयार कर नियमित रूप से अपने सुपरवाइजर के माध्यम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए। सभी बीएलओ को प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने बूथ पर उपस्थित रहना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बूथ पर प्राप्त फॉर्म-6 के प्रारूपों की तत्काल ऑनलाइन फीडिंग की जाए।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जल्द भर सकेंगे फर्राटा

» लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे सिक्स लेन हाई वे का लगभग काम पूरा हो चुका है

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। कानपुरङ्कलखनऊ एक्सप्रेसवे का उन्नाव क्षेत्र में 45.3 किलोमीटर लंबा खंड निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस खंड में रेलवे लाइन पर पुल निर्माण, टोल प्लाजा, मार्ग प्रकाश व्यवस्था और संकेतक जैसे सभी प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए तकनीकी परीक्षणों में उन्नाव से लखनऊ के बनी तक का यह पूरा हिस्सा मानकों पर खरा उतरा है। अब इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू करने के लिए लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में चल रहे शेष निर्माण कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

देश के आधुनिक हाईवेज में शामिल है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे

प्राधिकरण की योजना के अनुसार उन्नाव क्षेत्र को जोन दो के अंतर्गत रखा गया था, जहां कार्य तय समय में पूरा कर लिया गया है। मूल योजना के अनुसार इस जोन को जनवरी में ही यातायात के लिए खोल दिया जाना था, लेकिन लखनऊ क्षेत्र के जोन एक में 18.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से का निर्माण शेष होने के कारण पूरे एक्सप्रेसवे को एक साथ चालू करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण का मानना है कि दोनों जोन एक साथ शुरू होने से यात्रियों को निर्बाध और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

प्राधिकरण के परियोजना निदेशक नकुल कुमार वर्मा के अनुसार, उन्नाव क्षेत्र में एक्सप्रेसवे का समस्त निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लखनऊ क्षेत्र में बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने सहित कुछ तकनीकी कार्य शेष हैं, जिन्हें तेजी से पूरा कराया जा रहा है। लक्ष्य है कि 20 मार्च तक दोनों फेज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि आगे की औपचारिकताएं समय पर की जा सकें।

वहीं, निर्माण एजेंसी पीएनसी के डीजीएम प्रमोद बहेरा ने बताया कि उन्नाव में आजाद मार्ग चौराहा से बनी पुल तक, जोन दो का पूरा कार्य संपन्न हो चुका है। दोनों जोन का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर भी परियोजना की प्रगति की नियमित

समीक्षा की जा रही है। अनुमान है कि मार्च में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री द्वारा इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा सकता है।यह एक्सप्रेसवे न केवल कानपुर और लखनऊ के बीच यात्रा को तेज और सुगम बनाएगा, बल्कि यह प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लखनऊङ्ककानपुर मार्ग पर 10 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, स्वच्छ प्रसाधन गृह और एंबुलेंस सेवा जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।एक्सप्रेसवे के शुरू होने से कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को भी इससे नया गति मिलेगी। क्षेत्रीय विकास के लिहाज से यह परियोजना मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश की बुनियादी ढांचे की छवि भी और सुदृढ़ होगी।

आईजी की सख्ती

एक निरीक्षक सहित 13 पुलिसकर्मी निलंबित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोंडा। देवीपाटन रेंज में भ्रष्टाचार व विवेचनाओं में अनियमिताओं के चलते बेहद ईमानदार छवि के तेजतर्रार आईजी अमित पाठक ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक निरीक्षक और 12 उप निरीक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई विवेचनाओं में घूस लेकर बीमा का लाभ दिलाने और बीमा कंपनी का नुकसान करने का मामला सामने आने के बाद तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही को लेकर की गई है।बताते चले कि बीमा कंपनी से जुड़े राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आईजी अमित पाठक को दिये गये शिकायती प्रार्थना- पत्र में अंकित किया गया था कि जनपद गोण्डा,बहराइच व श्रीवास्तव में वाहन दुर्घटना से संबंधित मुकदमों में आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु घटना में प्रयुक्त वाहन को बदलकर उसके स्थान पर दूसरे वाहन को दिखाकर बीमा कम्पनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।इसी को लेकर आईजी अमित पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और एसआईटी टीम गठित कराकर जाँच करायी तो जनपद गोण्डा,बहराइच तथा श्रीवास्तव के 13 विवेचक दरोगा दोषी पाए गये जिसके बाद आईजी अमित पाठक ने बिना किसी देरी के तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए है।आईजी ने स्पष्ट किया है कि रेंज के किसी भी जनपद में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन समयबद्ध,पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए है.

भाकियू-कुर्मी शक्ति प्रदर्शन के आगे बैकफुट पर अयोध्या पुलिस

सड़क पर न्याय फाइलों में सौदेबाज़ी

» मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने 95 लोगों पर दर्ज किया था मुकदमा

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया FOLLOW UP

अयोध्या। कानून की किताबों में भले ही पुलिस को निष्पक्ष और निर्भीक बताया गया हो, लेकिन अयोध्या के गांधी पार्क में हुआ ÷हल्ला बोल÷ प्रदर्शन इस दावे की पोल खोलता नजर आया। कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन के दबाव में पुलिस को आखिरकार घुटने टेकने पड़े और दर्ज मुकदमा वापस लेने का लिखित आश्वासन देना पड़ा।

मामला थाना तारुन क्षेत्र के शिवकुमार वर्मा से जुड़ा है। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने आनन-फानन में 95 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप है कि जांच से पहले ही निर्दोषों को घसीट लिया गया। यही नहीं, मुकदमे में 51 मुकदमों वाले हिस्ट्रीशीटर दिलीप वर्मा का नाम जोड़कर पूरे प्रकरण को ÷संतुलित÷ दिखाने की कोशिश की गई। जब पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो सड़क ही अदालत बन गई। गांधी पार्क में हजारों लोग उतरे, नारे लगे, प्रशासन को घेरा गया। हालात इतने बिगड़े कि सिराथू विधायक पल्लवी पटेल को खुद धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने साफ कहा ÷जब तक समाज एक नहीं होगा, तब तक हक नहीं मिलेगा।सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय अब आंदोलन से मिलेगा? क्या बिना दबाव के पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती> एसपी ग्रामीण का लिखित आश्वासन इस बात का संकेत है कि मुकदमा जल्द ही कमजोर पड़ेगा। लेकिन यह भी साबित करता है कि कानून अब ताकत के तराजू पर तौला जा रहा है। आज कुर्मी समाज जीता है, कल कोई और सड़क पर उतरेगा। अगर यही व्यवस्था रही, तो थाने नहीं, धरने ही इंसाफ के केंद्र बन जाएंगे।

स्वराज इंडिया
स्वराज इंडिया अयोध्या
51 मुकदमों वाला कुख्यात अपराधी करा रहा 'महापंचायत'

सोहावल क्षेत्र की अवैध प्लाटिंग पर चला एडीए का बुलडोजर

कटरौली, सोहावल चौराहा और धन्नीपुर मस्जिद के सामने की गई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के सोहावल तहसील क्षेत्र में लंबे समय से फल-फूल रहे अवैध प्लॉटिंग के धंधे पर आखिरकार विकास प्राधिकरण ने करारा प्रहार कर दिया। बिना नक्शा पास कराए, बिना लेआउट प्लान और बिना किसी वैधानिक अनुमति के काटे गए प्लॉटों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।

यह कार्रवाई कटरौली, सोहावल चौराहा और धन्नीपुर मस्जिद के सामने की गई अवैध प्लॉटिंग पर की गई, जहां भूमाफियाओं ने खुलेआम खेतों को प्लॉट में तब्दील कर लोगों को बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे रहे। सूत्रों के मुताबिक, माफियाओं ने भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर लाखों रुपये वसूले, जबकि इन जमीनों का कोई वैधानिक रिकॉर्ड और स्वीकृत नक्शा मौजूद नहीं था।

न सड़क, न सीवर, न बिजली और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था–फिर भी प्लॉट धड़ल्ले से बेचे जाते रहे। जब शिकायतें बढ़ीं और मामला उच्च स्तर तक पहुंचा, तब जाकर विकास प्राधिकरण हरकत में आया। टीम ने मौके पर पहुंचकर लेआउट प्लान की जांच की, जिसमें कोई भी दस्तावेज वैध नहीं पाया गया।

इसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा था, तब स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग क्या कर रहा था? क्या यह लापरवाही थी या फिर माफियाओं को मौन संरक्षण? पड़ताल में सामने आया है कि सोहावल क्षेत्र में दर्जनों बीघा जमीन पर इसी तरह की अवैध प्लॉटिंग की जा चुकी है।

यदि समय रहते कार्रवाई न होती, तो यह इलाका अवैध कॉलोनियों का गढ़ बन जाता। विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई भले ही सराहनीय हो, लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि क्या यह अभियान लगातार चलेगा या फिर कुछ दिनों बाद माफिया फिर सिर उठाएंगे? लोगों का कहना है कि सिर्फ बुलडोजर चलाना ही नहीं, बल्कि इस अवैध कारोबार के सरगनाओं पर भी मुकदमा दर्ज हो, उनकी संपत्तियां जब्त हों और संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जवाबदेही तय हो।

कैशलेस चिकित्सा योजना पर भड़का यूटा

शिक्षकों ने योजना को बताया छलावा और भेदभावपूर्ण

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा), अयोध्या मंडल की इकाई ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक व परिषदीय शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों एवं रसोइयों के लिए लागू की गई कैशलेस चिकित्सा योजना को ÷छलावा मात्र÷ करार दिया है। इस संबंध में यूटा की एक बैठक आयोजित कर योजना की खामियों पर गंभीर सवाल उठाए गए।

बैठक में मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के नियमों और शर्तों में कोई स्पष्टता नहीं है। न तो अस्पतालों की सूची स्पष्ट है और न ही उपचार की सीमा तय की गई है। उन्होंने मांग की कि योजना को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएं। जिलाध्यक्ष अमित पाण्डेय ने योजना से जुड़ी संस्था ÷सांचीज÷ पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका नाम तक आम शिक्षकों को पता नहीं है। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों के लिए ओपीडी उपचार को भी योजना में शामिल किया जाए।

जिला महामंत्री रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि कोई शिक्षक अस्पताल में भर्ती होता है, तो भर्ती की तारीख से लेकर डिस्चार्ज के बाद मिलने वाली दवाइयों तक का पूरा खर्च योजना में शामिल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यह स्पष्ट नहीं है। जिला कोषाध्यक्ष गोविन्द कुमार वर्मा ने इसे वास्तविक कैशलेस योजना न बताते हुए सामान्य आयुष्मान कार्ड आधारित सुविधा बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड की अस्पतालों में स्वीकार्यता और प्रभावशीलता सभी जानते हैं। उन्होंने इसे शिक्षक समुदाय के साथ भेदभाव बताया। अंत में मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना शिक्षक समाज के लिए अस्वीकार्य है और सरकार को इसे संशोधित कर वास्तविक लाभकारी बनाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

बहू बेगम मकबरे पर माफिया राज

» बहू बेगम की वक्फ जमीन लूटने में सिस्टम की खुली साझेदारी!

» वक्फ संपत्ति पर अवैध दुकानें, पक्के मकान और टैक्सी स्टैंड बन चुके

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या आज जहां एक ओर आस्था और विरासत का वैश्विक केंद्र बन रही है, वहीं दूसरी ओर बहू बेगम साहिबा मकबरे की वक्फ जमीन पर खुलेआम माफिया राज कायम हो चुका है। ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है, वे या तो गहरी नींद में हैं या फिर मौन सहमति देकर कब्जेदारों को संरक्षण दे रहे हैं।

सैकड़ों साल पुरानी वक्फ संपत्ति पर अवैध दुकानें, पक्के मकान और टैक्सी स्टैंड खड़े हो चुके हैं। नियम, कानून और विरासत–तीनों को रौंदते हुए भूमाफिया बेखौफ निर्माण कर रहे हैं, और प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना बैठा है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा शिकार बना है विकलांग किराएदार रामानंद पांडे। दो बीघा जमीन पर खेती कर किसी तरह जीवन चला रहे रामानंद से दबंगों ने उसकी रोजी-रोटी छीन ली। जब उसने विरोध किया तो जवाब मिला–÷बोर्ड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।÷ यह धमकी नहीं, सिस्टम पर कब्जे का खुला ऐलान है।

नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर तक वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जों की लंबी फेहरिस्त है। शिकायतें हुईं, फोटो दिए गए, एजेंटों को बताया गया, लेकिन कार्रवाई शून्य। सवाल उठता है क्या यह लापरवाही है या फिर सुनियोजित साजिश?

वक्फ बोर्ड, नगर निगम और जिला प्रशासन तीनों की चुप्पी ने माफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। जब संरक्षित संपत्ति ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी की जमीन कौन बचाएगा? आज जरूरत है नोटिस नहीं, सीधी कार्रवाई की। बुलडोजर चले, कब्जे टूटें और जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरे। वरना आने वाले वर्षों में बहू बेगम मकबरा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा और उसकी जमीन माफियाओं की जागीर बन जाएगी।

आईसीओपी का होली मिलन समारोह 8 मार्च को

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। सर्किट हाउस में इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने की। बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूती पर मंथन किया गया।

जिलाध्यक्ष ने संगठन को तहसील स्तर तक फैलाने पर जोर दिया और 8 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने की जानकारी दी। मुख्य अतिथि जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान में सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में होली मिलन समारोह को भव्य बनाने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

कोहरे का कहर, 11 वाहन भिड़े, 15 घायल

डबल डेकर बस पलटी, श्रद्धालु जखमी

घने कोहरे ने जनजीवन ठप किया, सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर/आगरा। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत करीब 30 जिले इसकी चपेट में हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर मात्र 10 मीटर रह गई। कोहरे के चलते दो अलग-अलग सड़क हादसों में 11 वाहन आपस में टकरा गए, जिनमें 15 लोग घायल हो गए।

इटावा के जसवंतनगर क्षेत्र में आगरा हाईवे पर चारधाम व बरसाना दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मलाजनी गांव के पास हुए हादसे में बस में सवार 45 यात्रियों में से 10 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घने कोहरे के कारण आगरा एक्सप्रेस-वे पर भी यातायात प्रभावित रहा।

वहीं मेरठ के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे नंगली गेट के पास घने कोहरे में 11 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 4 पिकअप, 5 कार और 2 ट्रक शामिल रहे। चार लोग घायल हुए। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया।

- ❍ 30 जिले घने कोहरे की चपेट में
- ❍ विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमटी
- ❍ 2 हादसे, 11 वाहन टकराए, 15 घायल
- ❍ इटावा में डबल डेकर बस पलटी, 10 श्रद्धालु जखमी
- ❍ मेरठ हाईवे पर बड़ा जाम
- ❍ पारा 3-5 डिग्री गिरा, गलन बढ़ी
- ❍ 50+ ट्रेनें लेट, 4 फ्लाइट्स डिले

यातायात पर असरः ट्रेनें और फ्लाइट्स डिले

- ☛ कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं।
- ☛ लखनऊ, कानपुर समेत कई स्टेशनों पर 50 से अधिक ट्रेनें घंटों लेट रहीं।
- ☛ लखनऊ एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें डिले हुईं, जबकि एक दिन पहले 3 फ्लाइट्स रद्द रहीं।
- ☛ ठंड के चलते रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या भी कम नजर आई।

बिना कानूनी आदेश खाता फ्रीज किया तो बैंक पर पड़ेगा भारीः हाईकोर्ट

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- ➪ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस-बैंकों के लिए तय की सख्त गाइडलाइन
- ➪ साइबर फ्रॉड के नाम पर खाते फीज करने की मनमानी पर ब्रेक, 3-4 दिन में जब्ती आदेश अनिवार्य

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि कोई बैंक केवल पुलिस के अनुरोध पर, बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए, किसी व्यक्ति या संस्था का बैंक खाता फ्रीज करता है तो ऐसे बैंक को संबंधित व्यक्ति को हुई वित्तीय क्षति और प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान के लिए सिविल और आपराधिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने खालसा मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर यशवंत सिंह की याचिका पर यह निर्णय दिया। याची का खाता एक्सिस बैंक में था, जिसे हैदराबाद की राचकोंडा पुलिस द्वारा जारी नोटिस के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था। नोटिस में दावा किया गया था कि साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में पीड़ित के खाते से धोखाधड़ी की रकम याची के खाते में ट्रांसफर की गई है।

सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से स्वीकार किया गया कि नवंबर 2025 में डेबिट फ्रीज का नोटिस मिला था, लेकिन अब तक न तो कोई विधिवत जब्ती आदेश दिया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि किस राशि को फ्रीज किया जाना था। कोर्ट ने पाया कि नोटिस में न तो रकम का उल्लेख था और न ही बैंक को एफआईआर की प्रति या वैधानिक जब्ती आदेश उपलब्ध कराया गया। ऐसे में खाते को फ्रीज रखना कानूनन गलत

है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की आय को बचाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए खाता फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जांच अधिकारी का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह तीन से चार दिनों के भीतर बैंक को विधिवत जब्ती आदेश, संबंधित केस नंबर और वह सटीक राशि उपलब्ध कराए जिस पर लियन प्रस्तावित है।हाईकोर्ट ने इस फैसले के जरिए पुलिस और बैंकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि खातों को फ्रीज करने में मनमानी नहीं चलेगी और कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

बंद घर में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत

भूख-प्यास से तड़पकर टूट गई बुजुर्ग की सांस

स्वराज इंडिया न्यूज़ डेस्क

बठिंडा। बठिंडा के रामपुरा सिटी थाना क्षेत्र में एक बंद मकान के भीतर घटी यह घटना केवल एक खबर नहीं, बल्कि रिश्तों की दूरी और सामाजिक उदासीनता की मार्मिक तस्वीर बन गई है। यहां 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता रमेश कुमार ने अपने ही घर में भूख-प्यास से तड़पते हुए दम तोड़ दिया, जबकि उससे पहले उनके 50 वर्षीय बेटे संजय कुमार की मौत हो चुकी थी। करीब 12 दिनों तक दोनों के शव बंद घर में पड़े रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी।

पुलिस के मुताबिक रमेश कुमार और उनके पुत्र संजय कुमार मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे। रोज़गार और निजी कारणों से वे लंबे समय से बठिंडा के रामपुरा इलाके में रह रहे थे। पड़ोसियों के अनुसार पिता चलने-फिरने में असमर्थ थे और पूरी तरह बेटे पर निर्भर थे।

बेटे की मौत के बाद अकेले रह गए पिता: प्राथमिक जांच में सामने आया है कि संजय कुमार की अचानक मौत करीब 12 दिन पहले हुई। बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग पिता घर में अकेले फंस गए। शरीर जवाब दे चुका था, बाहर निकलने या किसी से मदद मांगने की स्थिति में नहीं थे। घर में न तो पर्याप्त भोजन था और न ही पानी। धीरे-धीरे भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ दिया और उन्होंने भी उसी घर में दम तोड़ दिया, जहां बेटे का शव पहले से पड़ा था।

- ➪ 12 दिनों तक बेटे का शव साथ रहा, लाचार पिता मदद के इंतजार में टूटता रहा
- ➪ फोन खामोश रहे, दरवाज़ा खुलते ही सामने आई इंसानियत को झकझोर देने वाली त्रासदी

फोन की खामोशी बनी अनहोनी की वजह

मृतक की बेटी ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से पिता और भाई को लगातार फोन कर रही थी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। पहले उसने सोचा कि नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जब 12-13 दिन बीत गए तो अनहोनी की आशंका गहराने लगी। वह रिश्तेदारों के साथ रामपुरा स्थित घर पहुंची। दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए कमरों में पसरी खामोशी और दो जिंदगियों का अंत।

दरवाजा बंद रहने पर भी शक नहीं हुआ

घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों का कहना है कि पिता-पुत्र ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, इसी वजह से किसी को लंबे समय तक दरवाजा बंद रहने पर भी शक नहीं हुआ। बदबू आने पर ही मामला उजागर हो सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने सहारा जनसेवा संस्था की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस विशेष रूप से संजय कुमार की मौत के कारण की जांच कर रही है। परिजनों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह परिस्थितियों की त्रासदी है। यह घटना समाज के लिए एक कड़वा सच है जहां पास रहते हुए भी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, और एक बुजुर्ग पिता अपने ही घर में मदद, पानी और एक इंसानी सहारे के इंतजार में जिंदगी हार गया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com